लिबोर से ट्रांजिशन कर रहे वित्तीय नियामक

सन्दर्भ:

- भारत में कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने अनुबंधों (लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट) LIBOR या संबंधित MIFOR (मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट) के संदर्भ में फ़ॉलबैक क्लॉज को शामिल नहीं किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- LIBOR और MIFOR दोनों 30 जून, 2023 से प्रतिनिधि बेंचमार्क नहीं रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संस्थाओं से अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने और आवश्यक कमियों को शामिल करने का आग्रह किया।

लिबोर विवाद:

- तंत्र दरों की रिपोर्टिंग बैंकों की ईमानदारी पर निर्भर करता है, जिससे संभावित हेराफेरी होती है।
- 2008 के वित्तीय संकट के दौरान जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बैंकों के पास दरों को कम बताने के लिए प्रोत्साहन थे।
- बैंकों द्वारा लाभ प्राप्ति के लिए प्रस्तुतियाँ बदलने और कम उधारी लागत का भुगतान करने के उदाहरण देखे गए हैं।
- ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन ने अप्रैल 2013 तक LIBOR को प्रशासित किया, जब यह FCA (वित्तीय आचरण प्राधिकरण) के दायरे में आया।

वैकल्पिक बेंचमार्क:

- अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2017 में LIBOR के विकल्प के रूप में सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR) की शुरुआत की।
- भारत में नए लेनदेन में MIFOR की जगह SOFR और संशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड
- एसओएफआर यू.एस. ट्रेजरी सिक्योरिटीज द्वारा संपार्श्विकृत अवलोकनीय रेपो दरों पर आधारित है, जो विशेषज्ञ निर्णय और संभावित हेरफेर पर निर्भरता को कम करता है।

भारत में प्रतिक्रिया:

- आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे लिबोर जोखिम का आकलन करें और वैकल्पिक संदर्भ दरों को अपनाने के लिए तैयार रहें।
- 31 दिसंबर, 2021 के बाद दर्ज किए गए अनुबंधों को संदर्भ दर के रूप में LIBOR का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- पारदर्शिता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तारीख से पहले किए गए अनुबंधों में फ़ॉलबैक खंड होने चाहिए।
- चूंकि SOFR आम तौर पर LIBOR से कम होता है, इस अंतर को ध्यान में रखते हुए कुछ समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निरंतरता और ग्राहक सुरक्षा के लिए अनुबंधों और समझौतों का आकलन और संशोधन करने की आवश्यकता है।

उद्देश्य और प्रभाव:

- इसका उद्देश्य जोखिमों का प्रबंधन करना, ग्राहकों की सुरक्षा करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।
- SOFR जैसे वैकल्पिक बेंचमार्क को अपनाकर,

आउटराइट रेट (MMIFOR) का उपयोग किया जाने लगा।	वित्तीय उद्योग हेरफेर की संभावना को कम कर सकता है और वित्तीय लेनदेन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर सकता है।

मानक देखभाल (Standard Care)

सन्दर्भ:

- भारत का लक्ष्य 2025 तक 75 मिलियन लोगों को उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए मानक देखभाल की सुविधा देना है।

मुख्य विशेषताएं:

- इस पहल का उद्देश्य रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम 80 प्रतिशत निदान किए गए व्यक्तियों को उचित उपचार मिले
- उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) तब होता है जब रक्त वाहिकाओं में दबाव बहुत अधिक (140/90 mmHg या अधिक) होता है।
- दुनिया भर में 30-79 वर्ष की आयु के अनुमानित 1.28 बिलियन वयस्कों को उच्च रक्तचाप है, जो अधिकांश (दो-तिहाई) निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं
- अनुमानित 46% उच्च रक्तचाप वाले वयस्क इस बात से अनजान हैं कि उन्हें यह स्थिति है।
- उच्च रक्तचाप वाले आधे से कम वयस्कों (42%) का निदान और उपचार किया जाता है।
- उच्च रक्तचाप वाले लगभग 5 में से 1 वयस्क (21%) ने इसे नियंत्रण में कर लिया है।
- मधुमेह एक पुरानी बीमारी है जो या तो तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है।
- इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है।
- हाइपरग्लाइकेमिया या बढ़ा हुआ रक्त शर्करा, अनियंत्रित मधुमेह का एक सामान्य प्रभाव है जो समय के साथ शरीर की कई प्रणालियों, विशेष रूप से नसों और रक्त वाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
- अनुमान है कि भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के 77 मिलियन लोग मधुमेह (टाइप 2) और लगभग 25 मिलियन प्रीडायबिटीज (निकट भविष्य में मधुमेह के विकास के उच्च जोखिम में) से पीड़ित हैं।
- 50% से अधिक लोग अपनी मधुमेह की स्थिति से अनजान हैं। यह अगर जल्दी पता नहीं लगाया गया और इलाज नहीं किया गया तो स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है।
- **ध्यान दें:** एक निश्चित प्रकार की बीमारी के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपचार को मानक देखभाल कहा जाता है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0

सन्दर्भ:

- सरकार ने 17,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है।

मुख्य विशेषताएं:

- इस योजना की अवधि छह साल है जिसमे अनुमानित निवेश 2,400 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
- इस फैसले से 75 हजार प्रत्यक्ष रोजगार सहित दो लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- इससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र पिछले आठ साल से लगातार सालाना 17 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है। इस अवधि में उत्पादन बढ़कर 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
- भारत मोबाइल फोन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है और मोबाइल फोन के निर्यात ने इस साल 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भी उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

उत्पादन से जुड़ी पहल क्या है?

- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) एक सरकारी योजना है जिसे भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने और कुछ क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है।
- पीएलआई योजना के तहत पात्र निर्माताओं को उनके वृद्धिशील उत्पादन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

उर्वरक सब्सिडी

सन्दर्भ:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिसमें फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपये और यूरिया सब्सिडी के लिए 70,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- उर्वरक सब्सिडी आम तौर पर ₹1 लाख करोड़ और ₹1.25 लाख करोड़ के बीच होती है, लेकिन पिछले साल यह ₹2.56 लाख करोड़ थी।
- सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सीजन के दौरान यूरिया और डायमोनियम
- इसी तरह, एनपीके पर प्रति बैग ₹1,639 की और एमओपी पर ₹734 की सब्सिडी है।
- खरीफ सीजन के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार 150 एलएमटी उर्वरक का स्टॉक रखती है।
- भारत अपनी कुल उर्वरक मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है।
- यूक्रेन संघर्ष के कारण 2022-23 में विभिन्न कृषि रसायनों की

फॉस्फेट (डीएपी) की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी।

- यूरिया की वर्तमान सब्सिडी दर ₹276 प्रति बैग है और डीएपी की कीमत ₹1,350 प्रति बैग है।
- इस निर्णय से लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
- **यूरिया की खपत:** देश में यूरिया की कुल खपत लगभग 325 से 350 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के साथ-साथ डीएपी, एनपीके और म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) की महत्वपूर्ण मात्रा है।
- देश भर में 1,400 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है, प्रति हेक्टेयर सब्सिडी लगभग ₹8,909 है, और प्रत्येक किसान को सब्सिडी में ₹21,223 प्राप्त होता है।
- डीएपी के एक बैग की वास्तविक कीमत ₹4,000 है, लेकिन किसानों को यह ₹2,461 की सब्सिडी के साथ ₹1,350 प्रति बैग की रियायती दर पर मिलता है।

वैश्विक कीमतें बहु-वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जिसके परिणामस्वरूप कुल उर्वरक सब्सिडी बिल रिकॉर्ड ₹2.56 लाख करोड़ हो गया।

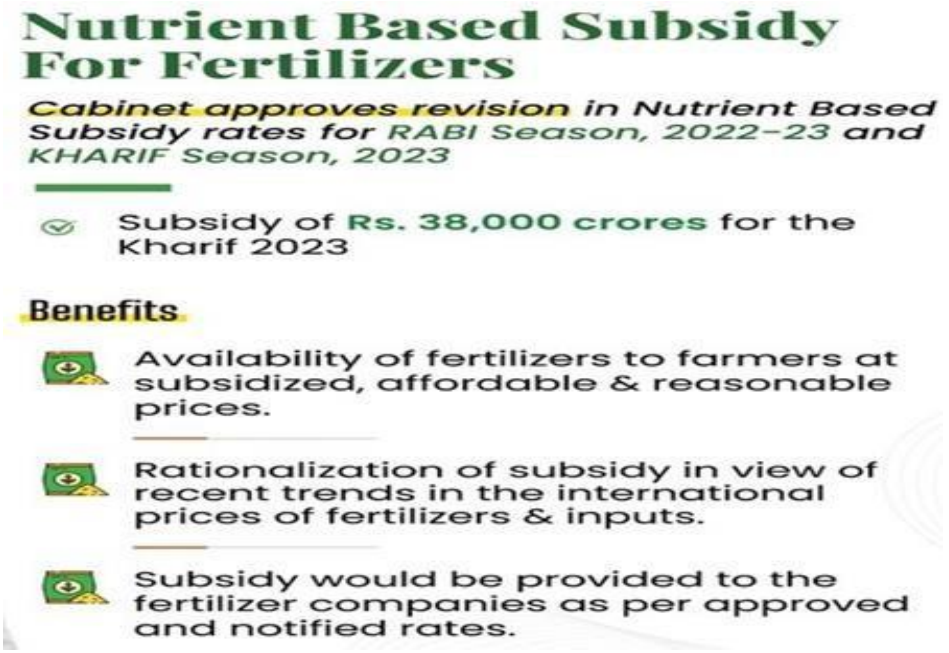

संक्षिप्तसुर्खियां

ऑपरेशन जल राहत

सन्दर्भ:

- भारतीय सेना के गजराज कोर और आपदा प्रबंधन समूहों ने असम में 'एक्सरसाइज जल राहत' नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत ड्रिल का आयोजन किया।

मुख्य विशेषताएं:

- इस अभ्यास का उद्देश्य मानसून के मौसम से पहले बाढ़ राहत तैयारियों को बढ़ाना है। इसने कई एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दिया और कुशल बचाव कार्यों और नवीन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया।

- भारतीय सेना, एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीएमए और पुलिस प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों के कर्मियों ने इस अभ्यास में भाग लिया।
- विशेषज्ञ टीमों के बीच संचार और सहयोग को ठीक करने के लिए बचाव अभियानों के लिए समन्वय और पूर्वाभ्यास आयोजित किए गए।
- इस ड्रिल ने स्थानीय संसाधनों के उपयोग और बाढ़ राहत कार्यों के दौरान स्थानीय सामग्रियों के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया।
- संयुक्त अभ्यास एजेंसियों को प्रयासों को सिंक्रनाइज़ करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और समन्वय अंतराल को संबोधित करने का अवसर प्रदान करता है।

गैर-चीनी मिठास

सन्दर्भ:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से रोकने और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के जोखिम को कम करने के लिए गैर-चीनी मिठास (non-communicable diseases) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- डिब्बाबंद भोजन और पेय पदार्थों में आमतौर पर गैर-चीनी मिठास जैसे कि एस्पार्टेम, स्टीविया और सकरीन का उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है।
- डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश बताते हैं कि एनएसएस वजन नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान नहीं करता है और इसके अवांछित प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और मृत्यु दर का बढ़ता जोखिम शामिल है।
- एनएसएस में पोषण मूल्य की कमी होती है जिसे आवश्यक आहार कारक नहीं माना जाता है। चीनी के सेवन को कम करने के वैकल्पिक तरीके जैसे कि फलों का सेवन या बिना चीनी वाले भोजन और पेय पदार्थों का पता लगाया जाना चाहिए।
- पहले से मौजूद मधुमेह वाले व्यक्तियों को छोड़कर एनएसएस के लिए दिशानिर्देश सामान्य आबादी पर लागू होती है।
- इसमें लो-कैलोरी शुगर या शुगर एल्कोहल शामिल नहीं है, जो एनएसएस से अलग हैं।
- दिशानिर्देश विशेष रूप से खाद्य और पेय पदार्थों में एनएसएस की खपत से संबंधित है और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता उत्पादों में उनके उपयोग तक विस्तृत नहीं है।
- WHO का उद्देश्य एनसीडी के जोखिम को कम करने और आजीवन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एनएसएस के उपयोग को हतोत्साहित करके दुनिया भर में

स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देना और आहार की गुणवत्ता में सुधार करना है।

गेको मिज़ोरामेंसिस

सन्दर्भ:

- मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के टूबिंगन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मिजोरम में एक नई प्रजाति की छिपकली की खोज की और उसका नामकरण किया।

मुख्य विशेषताएं:

- नई पहचानी गई प्रजाति का आधिकारिक नाम Gekko mizoramensis रखा गया है।
- यह शोध मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक संस्थान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था और हर्पेटोलॉजी पर एक प्रसिद्ध जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
- उड़न जेकॉस टाइकोजून उपजात से संबंधित हैं और पेड़ों के बीच सरकने की उनकी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
- गेको मिज़ोरामेन्सिस वृक्षों में पाया जाने वाला एक वृक्षीय प्राणी है, जो रात्रिचर गतिविधि प्रदर्शित करता है।
- डीएनए विश्लेषण के माध्यम से, शोधकर्ताओं ने Gekko mizoramensis और पहले से ज्ञात प्रजातियों Ptychozoon Lionotum के बीच अलग-अलग अंतर पाया।
- गेको मिजोरमेंसिस के नमूने मिजोरम के विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए थे, जिसमें वन्यजीव अभ्यारण्य और भंडार शामिल थे।

अफ़ग़ानिस्तान

सन्दर्भ:

- अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने मौलवी अब्दुल कबीर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह निर्णय तालिबान शासन के कार्यवाहक प्रमुख के खराब स्वास्थ्य के कारण अफगान तालिबान के सर्वोच्च नेता द्वारा लिया गया था।

राजनीतिक संरचना:

- अफगानिस्तान की सरकार, जिसे आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात कहा जाता है। अफगानिस्तान की एक एकात्मक राज्य की केंद्र सरकार है।

- यह सरकार तालिबान के नेतृत्व में एक धर्मतंत्र और अमीरात है, जिसमें राजनीतिक शक्ति एक सर्वोच्च नेता और उसके लिपिक सलाहकारों के हाथों में केंद्रित है, जिसे सामूहिक रूप से नेतृत्व कहा जाता है।
- नेतृत्व बंद दरवाजों के पीछे सभी प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है, जिन्हें देश की सिविल सेवा और न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है।
- अफगानिस्तान एक इस्लामी राज्य है, जिसका शासन शरिया पर आधारित है। इसे तालिबान व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के माध्यम से सख्ती से लागू करता है।
- **स्थान:** अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है।
- **सीमाएँ:** यह पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और उत्तर-पूर्व में चीन के साथ सीमा साझा करती है।

ट्रेकोमा

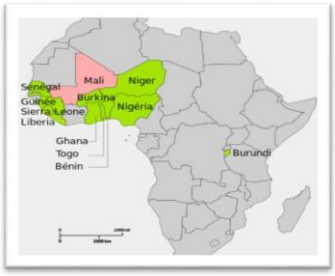

सन्दर्भ:

- बेनिन और माली ने अपने देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक ट्रेकोमा को खत्म कर दिया है।

मुख्य विशेषताएं:

- डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाई गई सुरक्षित रणनीति (सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, चेहरे की सफाई, पर्यावरण सुधार) ने ट्रेकोमा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- ट्रेकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है और यह आंख और नाक के स्राव के साथ-साथ मक्खियों से भी फैलता है।
- प्रगति के बावजूद, डब्ल्यूएचओ अफ्रीकी क्षेत्र के 23 देशों में ट्रेकोमा स्थानिकमारी वाला बना हुआ है। विश्व स्तर पर, घाना, गाम्बिया, टोगो और मलावी सहित 15 देशों ने ट्रेकोमा को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ मान्यता प्राप्त की है।

तुंगनाथ मंदिर

सन्दर्भ:

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने तुंगनाथ मंदिर पर एक अध्ययन कर पाया कि यह झुका हुआ है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह मंदिर गढ़वाल हिमालय के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और 12,800 फीट की

ऊंचाई पर स्थित है। एएसआई ने सिफारिश की है कि तुंगनाथ मंदिर को इसकी स्थापत्य विरासत को संरक्षित करने के लिए एक संरक्षित स्मारक के रूप में नामित किया जाए।

- सरकार ने मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस मामले पर सार्वजनिक इनपुट मांग रही है।
- तुंगनाथ मंदिर को दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसका बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर हिमालयी क्षेत्र में भक्ति और वास्तुकला की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है।

खासी जनजाति

सन्दर्भ:

- खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) ने एक निर्देश जारी किया है कि खासी वंश के व्यक्ति जो अपने पिता का उपनाम अपनाते हैं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

मुख्य विशेषताएं:

- जयंतिया और गारो के साथ खासी मेघालय में तीन स्वदेशी मातृसत्तात्मक समुदायों में से एक हैं।
- **मातृसत्तात्मक समाज:** खासी समाज की मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं, जहां माता के माध्यम से वंश और विरासत का पता लगाया जाता है, सबसे छोटी बेटी, जिसे "का खद्दूह" के रूप में जाना जाता है, विरासत में संपत्ति की हकदार होती है।
- इसके अधिकांश लोग आज ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जिनकी पारंपरिक मान्यताएं यू ब्ली नोंगथाव नामक व्यक्ति के अनुसार संचालित होती हैं।
- **त्यौहार:** खासी विभिन्न त्योहार मनाते हैं, कुछ प्रमुख त्योहारों में नोंगक्रेम नृत्य और शाद सुक म्यन्सीम शामिल हैं, जो पारंपरिक संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों का प्रदर्शन करते हैं।

ओडिशा मिलेट मिशन

सन्दर्भ:

- ओडिशा मिलेट मिशन (ओएमएम) ओडिशा सरकार द्वारा बाजरे की खेती को पुनर्जीवित करने और किसानों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्य विशेषताएं:

- ओएमएम ओडिशा मिलेट मिशन के तहत 600,000 क्विंटल से अधिक रागी की

	सफलतापूर्वक खरीद की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए एक सुरक्षित बाजार मिल रहा है। यह खरीद 3,578 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की गई है। • कोरापुट, रायगढ़ा, मल्कानगिरी, कालाहांडी, गजपति और सुंदरगढ़ सहित ओडिशा के दक्षिणी जिलों में सबसे अधिक रागी की खरीद हुई है। • सिस्टम ऑफ़ मिलेट इंटेन्सिफिकेशन (SMI) पद्धति को अपनाने से उपज में सुधार हुआ है, किसान अब प्रति एकड़ लगभग 5-6 क्विंटल की कटाई कर रहे हैं। • ओडिशा मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के बीच उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में स्थानीय गैर-लाभकारी, समुदाय-आधारित संगठनों और कृषि विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। • किसानों को कुशल प्रबंधन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाजरा खरीद और बिक्री (एमपीएएस) ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare